The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi):

State	Area (in hectares) (For which permits for extension of tea cultivation have been granted by Tea Board	
	1965-66	1966-67
Assam	4361·99	3840·57
West Bengal .	1981·09	628·00
Tripura .	80·35	..
Madras . .	432·08	307·98
Kerala . .	657·70	183·68
Mysore . . .	85·79	116·33

Production of Tea

5723. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of Commerce be pleased to state the progress made for bringing new areas under tea cultivation in different States and Union Territories; State-wise and Union Territory-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): Governments of States and Union Territories have been requested to undertake systematic surveys of areas suitable for extension of tea cultivation. There has been some progress in a few areas as indicated below:—

(i) NEFA—Applications of several enterpreneurs desirous of opening up tea plantations in this area, with the recommendations of the Tea Board thereon, are under consideration of the NEFA Administration.

(ii) Andaman & Nicobar Islands—A Study Team which investigated the possibility of opening up tea cultivation in these Islands in 1966 recommended that long term trials were necessary before any commercially based tea plantations could be started. The matter has accordingly been taken up with the Chief Commissioner, Andaman & Nicobar Islands.

(iii) JAMMU—A preliminary investigation has been carried out by a Study Team which has recommended both short and long term trials. The matter is being considered by the Jammu and Kashmir Government in consultation with the Tea Board.

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघे से बुने गये कपड़े की बिक्री

5724. **श्री मि० सू० मूर्ति :**
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री नच्चियार :
श्री गणेश घोष :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों की सहकारी समितियों को लगभग 75 लाख रुपये की छूट देनी है और उन्हों ने भी, इस तर्क पर कि उन के पास धन नहीं है, 1 जून, 1967 से उपभोक्ताओं को बुनकरों की सहकारी समितियों द्वारा हथकरघे से बुने हुए कपड़े की बिक्री पर छूट देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो छूट की देय राशि का भुगतान बुनकरों की सहकारी समितियों को तुरन्त करने और सहकारी क्षेत्र में हथकरघे से बुने हुए कपड़े की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राज्यों के समान उस राज्य में भी छूट योजना को पहले की भांति चालू रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) भुगतान आन्ध्र प्रदेश द्वारा किया जाना है । केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता की प्रणाली सभी सम्बद्ध राज्यों के विषय में एक सी होती है, अतः इस मामले पर आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ आवश्यक की जा रही है ।